



पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल

प्रलिस के लयल:

पीएम गतलशलकुतल योजनल, रलषुतुरीय अवसंरकनल डलइडललइन ।

डेनुस के लयल:

संसलधनुं कल संगुरहण, सरकलरी डकड, रलककुषीय नीतल, सरकलरी नीतयलँ और हसुतकषेड, पीएम गतलशलकुतल योजनल कल डहतुतुव ।

कुरकल डें कुयुं?

हलल ही डें डुरधलनडंतुरी के वकुरलन ["गतलशलकुतल"](#) (Gati Shakti) के अनुरुड डलरतीय रेल कल डहलल गतलशलकुतल कलरुगु टरुडनलल (Gati Shakti Cargo Terminal-GCT) डूरुवी रेलवे के असनसुल डंडल (Asansol Division) डें शुरु कयल गल है ।

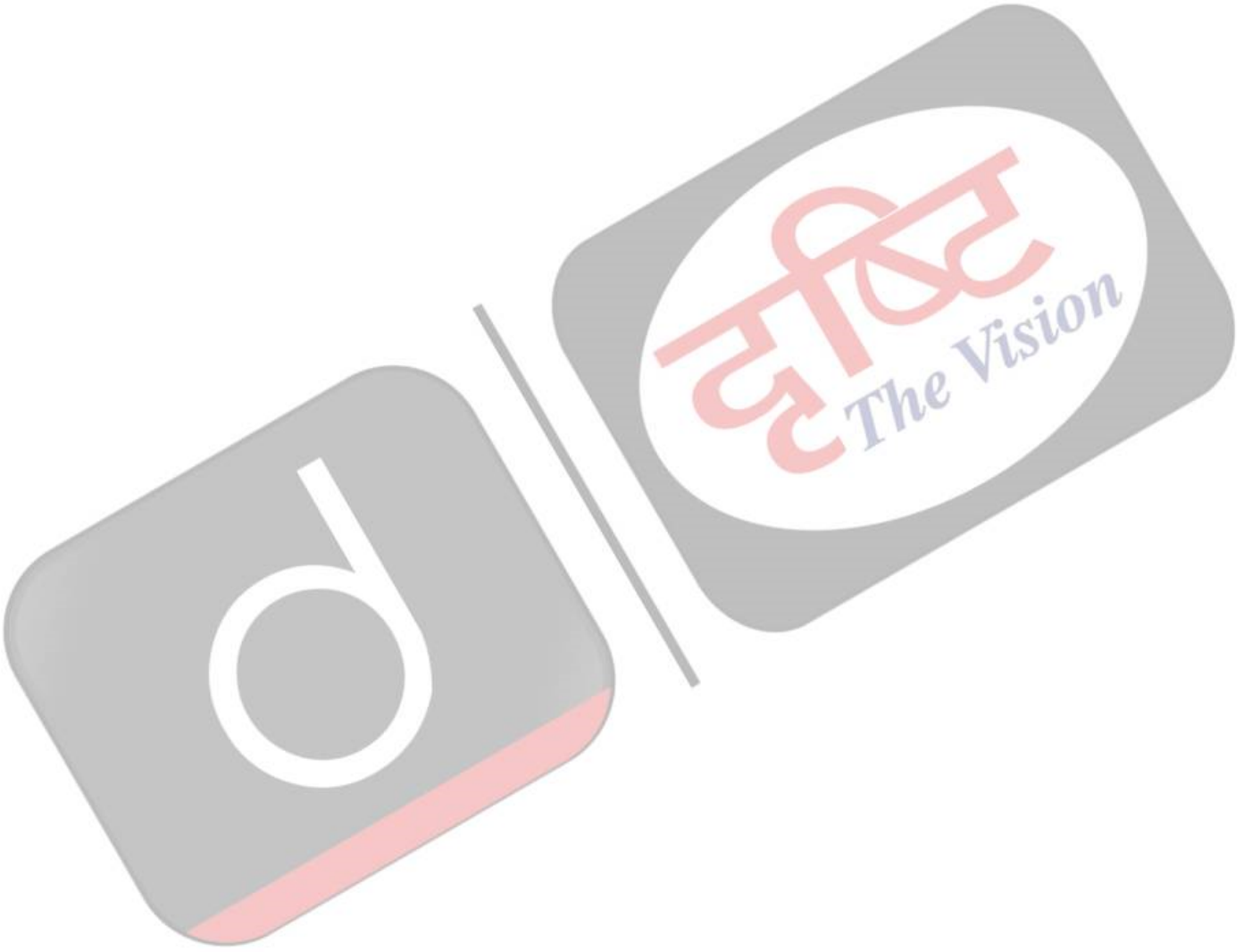
- डसलंडर '2021 डें GCT नीतल के ललगु हुने डलड से यह डलरतीय रेलवे डें इस तरह कल डहलल शकुतल कलरुगु टरुडनलल है ।
- इससे डलरतीय रेलवे की कडलई डें इकुरलडल हुने की उडुडी है । इस टरुडनलल और अनुड ऐसे टरुडनललस के कललु हुने से देश की अरुथवुडवसुथल डर सकरलरतुडक डुरडलव डड़ेगल ।

डुरडुख डलडु

डुरधलनडंतुरी गतलशलकुतल योजनल:

- डुरधलनडंतुरी गतलशलकुतल योजनल के डलरे डें:
 - वरुष 2021 डें डलरत सरकलर ने लुऑसलडकुस ललगत कु डक करुने के लयल सडनुवतल और डुनयलडी अवसंरकनल डरयलोजनलओं के नषलडलडन हेतु डहतुतुवलकलकुषी गतलशलकुतल योजनल यल 'नेशनल डलसुतर डुलन डुऑर डललुटी-डुऑल कनेकुतलवलडल डुलन' लुऑनुक कयल है ।
- उदुदेशुड:
 - कुरडीनी सुतर डर कलरुड डें तेकुरी ललने, ललगत कु डक करुने और रुऑगलर सुकुरन डर धुडलन देने के सलथ-सलथ अलगल डलर वरुषुं डें डुनयलडी अवसंरकनल डरयलोजनलओं की एकुकृत योजनल और कलरुडलनुवडन सुनशलकुतल करनल ।
 - गतलशलकुतल योजनल के तहत वरुष 2019 डें शुरु की गई 110 ललख कुरुडु रुडुए की '[रलषुतुरीय अवसंरकनल डलइडललइन](#)' कु शलडलल करनल ।
 - लुऑसलडकुस ललगत डें कटुती के अलवल इस योजनल कल उदुदेशुड कलरुगु हँडलगल कुषडतल कु डदुनल और वुडलडलर कु डदुवल देने हेतु डंडरगलहुं डर टरुनअरलउंड सडड कु डक करनल है ।
 - इसकल लकुषुड 11 [ऑदुडुगकु गलडलरुे](#) और डु नए [रकुषल गलडलरुे](#) (एक तडललनलडु डें और दूसरल उतुतर डुरदेश डें) डनलनल डल है ।
 - इसके तहत सडुी डुऑुं डें 4G कनेकुतलवलडल कल वसुतलर कयल कललगल । सलथ ही डुस डलइडललइन नेटवरुक डें 17,000 कललुडीतर की कुषडतल कुऑडुने की योजनल डनलई कल रलही है ।
 - यह वरुष 2024-25 के लयल सरकलर दुवलर नरलधलरतल डहतुतुवलकलकुषी लकुषुडुं कु डुरल करुने डें डदुद करुगल, कसलडें रलषुतुरीय रलकडलरुगु नेटवरुक की लंडलई कु 2 ललख कललुडीतर तक वसुतलरतल करनल, 200 से अधकल नए हवलई अडुडुं, हेलीडुऑरुट और वलटर एडुरुडुडुरुड कल नरुलडलण करनल शलडलल है ।

॥



■ अपेक्षति परणामः

- यह योजना मौजूदा और प्रस्तावति कनेक्टविटी परियोजनाओं की मैपिंग में मदद करेगी।
- साथ ही इसके माध्यम से देश में वभिन्न क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने संबंधी योजना भी स्पष्ट हो सकेगी।
- यह समग्र एवं एकीकृत परविहन कनेक्टविटी रणनीति 'मेक इन इंडिया' का समर्थन करेगी और परविहन के वभिन्न तरीकों को एकीकृत करेगी।
- इससे भारत को वशिव की व्यापारिक राजधानी बनने में मदद मलैगी।

■ एकीकृत बुनयादी अवसंरचना के वकिस की आवश्यकताः

- समन्वय एवं उन्नत सूचना साझाकरण की कमी के कारण वृहतस्तरीय नयोजन और सूक्ष्म स्तरीय कार्यान्वयन के बीच एक व्यापक अंतर मौजूद है, क्योंकि वभिन्न प्रायः अलगाव की स्थिति में कार्य करते हैं।
- एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% है, जो वकिसति देशों की तुलना में काफी अधिक है।
 - इस उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण भारत की नरियात प्रतस्पर्धात्मकता बहुत कम हो जाती है।
- वशिव स्तर पर यह स्वीकार कया जाता है कसित वकिस के लिये गुणवत्तापूर्ण बुनयादी अवसंरचना का नरिमाण काफी महत्त्वपूर्ण है, जो वभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से व्यापक पैमाने पर रोजगार पैदा करता है।
- इस योजना का कार्यान्वयन 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (NMP) के साथ समन्वय स्थापति कर कया जाएगा।
 - 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' को मुद्रीकरण हेतु एक स्पष्ट ढाँचा प्रदान करने और संभावति नविशकों को बेहतर रटिर्न की प्राप्ति के लिये संपत्तियों की एक सूची नरिमति करने हेतु शुरू कया गया है।

संबद्ध चतिाएँ:

- **लो क्रेडिट ऑफ-टेक:** हालाँकि सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिये कई सुधार कये हैं और [दवाला एवं दवालियापन संहति](#) ने खराब ऋणों पर लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए की वसूली की, इसके बावजूद ऋण लेने की प्रवृत्ति में गरिावट को लेकर चतिा व्यक्त की गई है।
 - भवषिय की आय और मौजूदा बाज़ार के प्रमाण के माध्यम से भवषिय की परियोजनाओं के वतितपोषण में व्यवसायों की मदद करने के लिये बैंक क्रेडिट ऑफ-टेक की सुवधि देते हैं।
- **मांग में कमी:** कोवडि-19 के बाद के परदृश्य में नजी मांग और नविश की कमी देखी गई है।
- **संरचनात्मक समस्याएँ:** भूमि अधगिरहण में देरी और मुकदमेबाज़ी के मुददों के कारण देश में वैश्विक मानकों की तुलना में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दर बहुत धीमी है।
 - इसके अतरिकित भूमि प्रयोग और पर्यावरण मंजूरी के मामले में वलिंब, अदालत में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे आदि अवसंरचना परियोजनाओं में देरी के कुछ प्रमुख कारण हैं।

आगे की राह

- PM गति शक्ति सही दशिा में उठाया गया एक कदम है। हालाँकि इसके उच्च सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न संरचनात्मक और व्यापक आर्थिक स्थरिता संबंधी चतिाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
 - इस प्रकार आवश्यक है कयिह पहल एक स्थरि और पूरवानुमेय नयिमक एवं संस्थागत ढाँचे पर आधारति हो।

वगित वर्षों के प्रश्नः

प्र. हाल ही में भारत का पहला 'राष्ट्रीय नविश और वनिरिमाण क्षेत्र' कहाँ स्थापति करने का प्रस्ताव कया गया था? (2016)

- (a) आंध्र प्रदेश
- (b) गुजरात
- (c) महाराष्ट्र
- (d) उत्तर प्रदेश

उत्तर: (a)

स्रोतः पी.आई.बी.